प्रसंगशः

आलोक मेहता

नाजायज नहीं चिंता अपनी जमीन की

आजादी से पहले गोविंद वल्लभ पंत ने भी किसानों और मुसलमानों को दिखाई थी दिशा

किसान और मुसलमान की चिंता किए बिना कांग्रेस की नैया कभी पार नहीं हो सकती। नैनीताल में कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की चिंता पर केंद्र सरकार में बैठे उदारवादी नेताओं को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कुछ ही महीनों बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी को गांवों में यह साबित करना होगा कि उसने आर्थिक चकाचौंध में अपनी पारंपरिक प्राथमिकताओं को भुलाया नहीं है। इसी तरह मोतीलाल वोरा, नारायण दत्त तिवारी, बलराम जाखड़, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह जैसे असली कांग्रेसी नेता केंद्र सरकार में बैठे आधुनिकतम नेताओं को किसानों और अल्पसंख्यकों के लिए आजादी से पहले भी रही प्रतिबद्धता से अवगत करा दें। इस दृष्टि से पं. गोविंद वल्लभ पंत द्वारा निरंतर उठाई गई बातों को याद दिलाना अधिक उचित होगा। पंतजी ने 13 नवंबर, 1937 को रायबरेली की एक सभा में तत्कालीन यूनाइटेड प्रॉविंस (यू.पी.) के प्रधानमंत्री (अब की भाषा में मुख्यमंत्री) रहते हुए कहा था, 'लोग मुझे भले ही प्रदेश प्रमुख के रूप में जानते हों, मैं अपने को जनता के बीच का साधारण कार्यकर्ता और एक किसान मानता हूं। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूखे किसानों की हालत सुधार कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना होगी। किसानों को प्रशासनिक भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।' आजादी से पहले राज्य एक हद तक स्वायत्तता के अंतर्गत कांग्रेसी सत्ता में आ गए थे लेकिन ब्रिटिश प्रशासन के जुल्मों और भ्रष्टाचार से किसान त्राहिमाम कर रहे थे। पंतजी ने उन्हीं दिनों कांग्रेसजनों से आग्रह किया था कि वे जनता से कर के रूप में मिलने वाली एक पाई का भी दुरुपयोग न होने दें। महात्मा गांधी के पदचिह्नों पर चलने वाले गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद भाषणों और पत्रों के माध्यम से कांग्रेसी मंत्रियों को चेतावनी भी दे रहे थे। जवाहरलाल जी ने 1937 में ही राज्यों के तत्कालीन मंत्रियों के रवैये को लेकर गहरी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए पंतजी को भी पत्र लिखा था। इसे देश का दुर्भाग्य ही माना जाएगा कि गरीबी उन्मूलन, किसानों के उत्थान और भ्रष्टाचार से मुक्ति का यह सपना अब भी अधूरा है।

जमीन से जुड़े पुराने कांग्रेसी नेताओं ने गांवों के पुनर्निर्माण के लिए किसानों की कुटीर उद्योगों में भागीदारी पर जोर दिया। हां, नेहरू या पंत जैसे नेता किसानों द्वारा लगान चुकाने की आवश्यकता समझाते थे। वर्तमान नेताओं की तरह मुफ्त बिजली जैसे फॉर्मूलों को अपनाने के बजाय उन्हें जागरूक बनाकर राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनाना उपयुक्त समझते थे। कांग्रेस या अन्य प्रभावशाली राजनीतिक दलों के कुछ नेताओं ने पिछले वर्षों के दौरान वोट राजनीति के चक्कर में किसानों को बेहद बरगलाया और उन्हें गलत रास्ते दिखाए। खासकर पंचायत में प्रभावशाली होने वालों को खाने-कमाने के मोह में डालने से कई इलाकों में निचले स्तर पर ग्रामीण-विकास के बजट में हेराफेरी होने लगी। दूसरी तरफ औद्योगिक विकास के अभियान में लगे नेताओं ने विभिन्न राज्यों में विशेष आर्थिक जोन विकसित करने के लिए हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहण का सिलसिला शुरू किया। इसमें कोई शक नहीं कि अर्थ-व्यवस्था को केवल कृषि पर निर्भर नहीं रखकर, औद्योगिक विकास से अधिक रोजगार और बेहतर जिंदगी के अवसर उपलब्ध किए जा सकते हैं, खासकर जिन इलाकों में प्राकृतिक कृपा पर्याप्त न होने तथा खेतीबाड़ी से लोगों के पेट न भर पाने की स्थितियां हैं। लेकिन इस अभियान में सरकार की नीयत साफ न होने एवं किसानों के हितों की कीमत पर बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की धारणा बनना बेहद खतरनाक है। नैनीताल में स्वयं सोनिया गांधी को इस मामले में चेतावनी देनी पड़ी। लेकिन आवश्यकता इस बात की भी है कि कृषि तथा औद्योगिक विकास की सफलता और संतुलन के लिए केंद्र या राज्य सरकारें पहले ग्रामीणों को जागरूक बनाने का अभियान चलाएं और इस बात की न्यूनतम गारंटी दें कि जमीन के उपयुक्त मूल्य के अलावा नई औद्योगिक बस्ती विकसित होने पर उसी क्षेत्र के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी। अन्यथा अकारण सामाजिक अशांति पैदा करने में माहिर विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे नेता विध्वंसकारी स्थितियां पैदा करते रहेंगे। मजेदार बात यह है कि पुराने जहरीले अनुभवों के बावजूद कांग्रेस के कुछ नेता आगामी चुनावों में भिंडरांवाले की तरह अप्रत्यक्ष रूप से विश्वनाथ प्रताप सिंह का इस्तेमाल करने की फिराक में हैं। अमेरिका या पाकिस्तान के शासक बिन लादेन को मोहरा बनाकर गंभीर नतीजे आज तक भुगत रहे हैं। भारत में सभी पार्टियां वि.प्र. सिंह और जॉर्ज फर्नांडीस की पिटी-पिटाई साख और समाज में विघटनकारी परिस्थितियां बनाने की प्रवृत्ति जानते हुए भी उन्हें आजमाने की गलती करती रही हैं। गरीब अशिक्षित किसानों और अल्पसंख्यकों के लिए यह सबसे बड़ी ज्यादती है।

अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर भी राष्ट्रीय या कुछ क्षेत्रीय दलों में अजीब सी होड़ लगी रहती है। इस राजनीतिक खींचातानी में बहुसंख्यक वर्ग भी भ्रमित होता है और सांप्रदायिक संगठनों को भड़काने के अवसर मिलते हैं। पिछले महीनों के दौरान मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी विवाद पैदा हुआ लेकिन किसी पक्ष ने आजादी से पहले रही स्थिति के तथ्य सामने रखकर लोगों को समझाने का प्रयास नहीं किया। इस संदर्भ में एक बार फिर उत्तर प्रदेश के सरकारी रिकॉर्ड से 11 जनवरी, 1939 को तत्कालीन प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा प्रेस सलाहकार समिति के समक्ष रखे गए तथ्यों का उल्लेख जरूरी लगता है। पंतजी ने इस बैठक में बताया, 'प्रदेश की करीब 14 प्रतिशत आबादी मुस्लिम है तथा लगभग 5 प्रतिशत गैर-हिंदू और गैर-मुस्लिम हैं। इस तरह 80 से 85 प्रतिशत हिंदू आबादी है। जबकि प्रादेशिक प्रशासनिक सेवाओं में 52.5 प्रतिशत हिंदू और 39.6 प्रतिशत मुस्लिम हैं। विभिन्न पदों पर तैनात अधिकारियों में तहसीलदार 55.9 प्रतिशत हिंदू तथा 43.6 प्रतिशत मुस्लिम, नायब तहसीलदार, 55.9 प्रतिशत हिंदू तथा 41.1 प्रतिशत मुस्लिम, प्रादेशिक न्यायिक अधिकारी 72 प्रतिशत हिंदू तथा 25 प्रतिशत मुस्लिम, पुलिस उप अधीक्षक 46.4 प्रतिशत हिंदू तथा 30 प्रतिशत मुस्लिम, उप निरीक्षक 54.2 प्रतिशत हिंदू तथा 43.8 प्रतिशत मुस्लिम, हेड कांस्टेबल 35.3 प्रतिशत हिंदू तथा 64.4 प्रतिशत मुस्लिम कार्यरत हैं।' इन आंकड़ों के जरिये पंतजी ने यह विश्वास दिलाने की कोशिश की थी कि आबादी के अनुपात में अल्पसंख्यकों को नौकरियों में समुचित महत्व मिला। उस समय आरक्षण की बीमारी नहीं फैली थी। यदि 70 साल पहले कांग्रेस की राज्य सरकारें अल्पसंख्यकों को समुचित महत्व देकर उनका विश्वास जीत सकती थीं तो आजादी के बाद अब आर्थिक आत्मनिर्भरता के दौर में अल्पसंख्यकों को हर क्षेत्र में समुचित स्थान देने पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा सकता? यह काम भी वोट राजनीति का हिस्सा न होकर सामाजिक-आर्थिक उन्नति के अभियान के महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में होना चाहिए। किसान, मजदूर, शिक्षक, व्यापारी, उद्योगपति, अगड़ा-पिछड़ा या अल्पसंख्यक- हर वर्ग राष्ट्रीय विकास में अहम भूमिका निभाता है। राजनीतिक दल उसको सही दिशा देने तथा उसके बल पर समाज तथा राष्ट्र को अधिक सशक्त और संपन्न बनाने पर पूरा ध्यान दें तो संभवतः भारत से अधिक शक्तिशाली देश दुनिया में कोई नहीं होगा। ●

> आवश्यकता इस बात की भी है कि कृषि तथा औद्योगिक विकास की सफलता के लिए सरकारें ग्रामीणों को जागरूक बनाएं।